

**न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर**

*आंश-1859-PBM/C*  
/2016 पुनरीक्षण

प्रकरण कमांक

श्री. *बृजमोहन*  
तारासेवनिया  
प्र० 916-116

1. परमानन्द पुत्र श्री रामफूल देशवाली
2. प्रतापसिंह पुत्र श्री परमानन्द देशवाली  
निवासीगण- ग्राम तारासेवनिया, तहसील  
हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

महानगर न्यायालय कोर्ट  
राजस्थान राज्य न्यायालय

*प्रस्ताव द्वारा अर्जित  
श्री परमानन्द  
श्री बृजमोहन  
09-6-16*

---आवेदकगण

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री रामफूल देशवाली  
निवासी- ग्राम तारासेवनिया, तहसील  
हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०
2. रामानन्द पुत्र श्री भगवानसिंह निवासी-  
ग्राम चरनाल तहसील व जिला सीहोर,  
(म०प्र०) ---अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30/01/2016 पारित द्वारा  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर  
जिला भोपाल, म०प्र० के प्रकरण कमांक  
20/अपील/15-16 व उनवान बृजमोहन आदि बनाम  
परमानन्द आदि ।

गानगीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

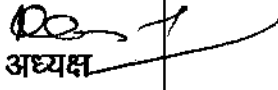
*Om Singh*



**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक निग.1859-पीबीआर/2016 [चरमानंद/इ.ज.मोहन] जिला भोपाल**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पत्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर  |
|------------------|--|---|
| 9-6-2016         | <p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-1-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म0प्र0भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 52 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अधिकतम 3 माह के लिये स्थगन दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आगामी आदेश तक तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20-10-15 का क्रियान्वयन स्थगित करने में संहिता के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि उनके द्वारा अनेक पेशियों पर स्थगन निरस्त किये जाने संबंधी लिखित एवं मौखिक अनुरोध करने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन निरस्त नहीं किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः 7-6-16 को स्थगन निरस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस पेशी दिनांक को भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन निरस्त नहीं करने के कारण यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20-10-2015 का क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है, जबकि संहिता की धारा 52 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अधिकतम 3 माह के लिये कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह में प्रकरण का निराकरण करें ।</p> | <p align="right"> <br/> <b>अध्यक्ष</b> </p> |

